nt>
Title: Need to create facilities for primary and higher education in the backward area of Mayurbhanj District in Orissa.

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : सभापति जी, मैं आपके ध्यान में आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में घोर अवहेलना का मामला लाना चाहता हूं। उड़ीसा प्रांत में मयूरभंज जिला, जहां से मैं आता हूं, वहां प्राइमरी और हायर एजुकेशन, दोनों ही मामलों में उड़ीसा सरकार का रवैया अपमानजनक और निन्दनीय है। वहां अभी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी है। लगभग १६०० शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है। प्रायः उड़ीसा के सभी जिलों में ये नियुक्तियां हो गई हैं, किंतु मयूरभंज जिले में अभी तक नहीं हुई हैं। यह जिला आदिवासी बहुल जिला है, जहां शिक्षा की काफी आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि वहां शिक्षकों की नियुक्ति अविलम्ब की जाए। उच्च स्तरीय शिक्षा के मामले में दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि वर्तमान उड़ीसा सरकार ने नार्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी, जिसके तहत मयूरभंज के अंदर सुंदरगढ़,क्योंझर और बालेश्वर आदि आदिवासी और पिछड़े जिलों को कवर करने की बात थी। बारीपदा जो मयूरभंज जिले का मुख्यालय है, वहां इसका मुख्यालय होना चाहिए, किंतु सरकार ने इसका मुख्यालय भुवनेश्वर बना दिया, यानी उत्तर की जगह दक्षिण में बना दिया। इसके लिए जस्टिस एस.के. मोहन्ती की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई थी।

एस.के. मोहन्ती की रिपोर्ट को उड़ीसा सरकार न विधान संविधान सभा में रख रही है और न ही जनता के सामने ला रही है। इस स्थिति में इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय शिक्षा की अवहेलना जारी रहेगी और आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाएगा। इस प्रकार उस क्षेत्र का शोषण किया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त कार्यों को अविलम्ब किया जाए।